भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 521

बुधवार, 06 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
विश्व आर्थिक मंच

521. श्री संजय काका पाटिल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की निवेश क्षमता को रेखांकित करने के लिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मंचों पर युवाओं को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): सरकार ने आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा वृद्धि और विकास के अधिक अवसरों का सृजन करते हुए निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। ऐसी एक पहल के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य निवेश की सुविधा प्रदान करना, नवप्रयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्कृष्ट अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। इन नीतिगत उपायों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज, चौदह (14) क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। उपर्युक्त सभी पहलों/स्कीमों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया जाता है।

वि भिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनस में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता

नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय आदि शामिल हैं।

सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों/पहलों आदि के माध्यम से भारत की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों और फोरमों का उपयोग करती है। ऐसा ही एक प्लेटफार्म विश्व आर्थिक मंच है, जो दावोस में अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन करता है।

(ग) और (घ) : सरकार ने देश में नवप्रयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए हैं। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी पहल है, जिसके तहत ऐसे युवा उद्यमियों ने नई प्रौद्योगिकीय समाधानों का प्रयोग करते हुए कई कंपनियां स्थापित की हैं, जिनके पास निवेश क्षमता वाले आइडिया हैं। ऐसे युवा उद्यमी भारत में निवेश अवसरों को बढ़ावा देते हुए ऐसे फोरम में भी भाग लेते हैं।

*****